मुख्यमंत्री के निर्देश : विधायक अतिवृष्टि क्षेत्र का सघन निरीक्षण करें

प्रभारी मंत्रियों व सचिवों को भी दो दिन जिलों में राहत व बचाव कार्य की निगरानी के निर्देश दिए

जयपुर, 4 सितंबर। राजस्थान में अतिवृष्टि के कारण उत्पन्न हालात को देखते हुए, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सभी विधायकों को 5, 6 एवं 7 सितंबर को अपने-अपने विधानसभा क्षेत्रों का सघन निरीक्षण करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि जनप्रतिनिधि संवेदनशीलता और तत्परता के साथ आमजन की समस्याओं का समाधान करें।

मुख्यमंत्री ने प्रभारी मंत्रियों और सचिवों को भी निर्देशित किया है कि वे दो दिन तक जिलों का दौरा कर राहत और बचाव कार्यों की निगरानी करें तथा आमजन की समस्याओं का प्राथमिकता से निस्तारण कराएं। भारी बारिश से बनी स्थिति को लेकर विधानसभा में चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री ने बताया कि इस वर्ष 1 जून से 1 सितंबर तक प्रदेश में औसत से 56 प्रतिशत अधिक वर्षा हुई है। ऐसे में सभी विधायक अपने क्षेत्रों में सक्रिय भूमिका निभाएं और जिला प्रशासन के साथ समन्वय कर राहत कार्यों को गति दें।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा

मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि विधायक और प्रभारी मंत्री अपने-अपने क्षेत्रों में जिला कलेक्टर व अन्य अधिकारियों के साथ नियमित बैठकें करें और राहत कार्यों की प्रगति की जानकारी लें। साथ ही, प्रभावित क्षेत्रों में जाकर लोगों का मनोबल बढ़ाएं। उन्होंने कहा कि निचले इलाकों से समय रहते लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जाए और भोजन पैकेट, पीने का पानी, दवाइयां व कपड़े जैसी जरूरी सामग्री की आपूर्ति सुनिश्चित की जाए।

■ **मुख्यमंत्री ने कहा कि विधायक नियमित रूप से मीडिया व आम जन को राहत कार्यों की जानकारी दें ताकि किसी प्रकार की अफवाह नहीं फैले।**

महिलाओं, बच्चों, बुजुर्गों और दिव्यांगजनों के लिए सुरक्षित अस्थायी आश्रय की व्यवस्था कराने के भी निर्देश दिए गए हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि विधायक नियमित रूप से मीडिया और आमजन को राहत कार्यों की जानकारी दें, ताकि किसी प्रकार की अफवाह न फैले। सोशल मीडिया पर भी हेल्पलाइन नंबर और राहत कार्यों की जानकारी साझा की जाए। उन्होंने प्रभावित क्षेत्रों में चिकित्सा टीमों की तैनाती, पशुओं के टीकाकरण, पेयजल स्रोतों के क्लोरीनेशन, शिविरों में स्वच्छता की निगरानी और लोगों को गंदे पानी से दूर रहने व साफ भोजन-पानी के लिए जागरूक करने के निर्देश भी दिए।

सरकार ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

तंबाकू, कच्चा तंबाकू और तंबाकू अपशिष्ट, सिगार, चेरूट्स, सिगारिलोस, तंबाकू के विकल्प, वातित पेय (एयरेटेड ड्रिंक्स), कार्बोनेटेड पेय (फल-आधारित भी), कैफीन युक्त पेय, 1,200 सीसी (पेट्रोल) या 1,500 सीसी (डीजल) से बड़ी कार, 350 सीसी से अधिक क्षमता वाली मोटरसाइकिलें, यॉट्स (निजी नौकाएँ), निजी उपयोग के लिए विमान, रेसिंग कार, ऑनलाइन जुआ और गेमिंग प्लेटफॉर्म। इनमें से अधिकांश वस्तुओं पर पहले ही 28 जीएसटी और क्षतिपूरक उपकर लग रहा था, जिससे कुल कर भार लगभग 40 तक पहुँच रहा था। जीएसटी परिषद ने 12 प्रतिशत और 28 प्रतिशत की दरों को समाप्त कर दिया है और संरचना को केवल दो स्लैब में समेट दिया है: 5 प्रतिशत और 18 प्रतिशत। टूथपेस्ट, साबुन, शैम्पू, छोटी कारें, टेलीविज़न, और एयर कंडीशनर जैसी रोज़मर्रा की वस्तुएँ अब कम कर-दरों में आएँगी। बहुत सी दवाएँ, दैनिक उपयोग की वस्तुएँ और चिकित्सा-ग्रेड ऑक्सीजन या तो कर-मुक्त कर दी गई हैं या 5 प्रतिशत स्लैब में लाई गई हैं।

सीजन में पहली बार माही बांध के सभी 16 गेट खोले

अगस्त में 4 गेट खोल कर पानी की निकासी की गयी थी, पर कैचमेंट क्षेत्र से पानी की आवक बढ़ती गयी

उदयपुर, 4 सितम्बर (कासं)। विदाई से पहले, मेवाड़-वागड़ के कई भागों में मध्यम से तेज बारिश का दौर जारी है। पिछले 24 घंटों में उदयपुर जिले के खेरवाड़ा में 81 मिलीमीटर बारिश हुई। कई जलाशयों में पानी की आवक लगातार बनी हुई है।

कैचमेंट में अच्छी बारिश होने और पानी की आवक तेज होने पर गुरूवार को बांसवाड़ा जिले में स्थित माही बांध के सभी 16 गेट खोल दिए गए। इस सीजन में पहली बार माही बांध के सभी 16 गेट खोले गए हैं। अगस्त में इस बांध के 4 गेट खोलकर पानी की निकासी शुरू की गई थी। उसके बाद आवक बनी रही तो पिछले दिनों और ज्यादा गेट खोले गए। लगातार निकासी के बावजूद, पिछले 24 घंटों में कैचमेंट से पानी की आवक और तेज होने पर पानी की निकासी के लिए बांध के सभी 16 गेट खोल दिए गए।

■ **उदयपुर की आयड़ नदी से पिछोला में आवक बनी हुई है। दोनों गेट तीन फीट खोलने के बाद भी उदय सागर का जलस्तर बढ़ रहा है।**

जलसंसाधन विभाग के अनुसार, पिछले 24 घंटों में उदयपुर जिले के खेरवाड़ा में 81 मिलीमीटर, ऋषभदेव में 55, नया गांव में 50, वल्लभनगर में 42, सोमकागदर में 40, सलूंबर में 63, दानपुर बांसवाडा में 65, भदेसर चित्तौड में 48, वागन डेम प्रतापगढ़ में 91 और अरनोद में 58 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। मदार नहर से फतहसागर और सीसारमा नदी से पिछोला में आवक जारी है। आयड़ नदी से उदयसागर में आवक बनी हुई है। दोनों गेट तीन-तीन फीट खोल रखे हैं। उसके बावजूद उदयसागर का जलस्तर बढ़ ही रहा है। पिछले 24 घंटों में उदयसागर के जलस्तर में 2 इंच की बढ़ोतरी हुई है। मादड़ी बांध का गेज 34 फीट के मुकाबले 33 हो गया है। टनल का गेट 6 इंच खोलकर पानी पिछोला में डायवर्ट किया जा रहा है। देवास प्रथम बांध का पानी भी टनल से पिछोला डायवर्ट कर रखा है। देवास प्रथम बांध दो फीट ही खाली है।

अजमेर : बोराज तालाब की पाल में रिसाव, स्वास्तिक नगर के 80 मकान खाली कराये

जिला प्रशासन को आशंका है कि दरार व रिसाव के कारण तालाब की पाल कभी भी टूट सकती है

अजमेर, 4 सितम्बर (कासं)। गुरुवार सुबह से हो रही बरसात से शहर की सड़कें दरिया बनी गईं तो वहीं निचली बस्तियों में पानी भरने से लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग ने आगामी दो-तीन दिनों में तेज बारिश की संभावना जताई है। आम का तालाब क्षेत्र की कॉलोनी में बरसात का पानी भरने से लोग नारकीय जीवन जीने पर मजबूर हो गए हैं। वहीं, बारिश से बोराज तालाब लबालब होने से पाल में आई दरार और रिसाव की आशंका के चलते जिला प्रशासन ने फायसागर रोड स्थित स्वास्तिक नगर कॉलोनी के करीब 80 मकानों को खाली कराया है। प्रभावित परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। लगातार बारिश से तालाब की पाल पर दबाव बढ़ रहा है, जिससे पाल कभी भी टूट सकती है। तालाब क्षेत्र के

■ **तालाब क्षेत्र के बोराज गांव, रावत नगर व स्वास्तिक नगर सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र हैं। एन. डी. आर. एफ. और सिविल डिफेन्स की टीमें भी तैनात कर दी गई हैं।**

बोराज गांव, रावत नगर व स्वास्तिक नगर सबसे अधिक प्रभावित हैं, कई घरों में पानी भरा हुआ है।

जानकारी के अनुसार, गुरुवार सुबह से तेज बारिश का दौर शुरू हुआ, जो दोपहर तक रिमझिम फुहार के रूप में जारी रहा, जिससे मुख्य सड़कों पर पानी भर गया तथा वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लगातार बारिश के अलर्ट को देखते हुए जिला प्रशासन द्वारा निगरानी रखी जा रही है। मौसम विभाग के अनुसार दो-तीन दिन अजमेर संभाग के कई इलाकों में कहीं-कहीं मध्य से तेज बारिश की संभावना है। मानसून के इस सीजन में अब तक एक हजार एमएम बारिश रिकार्ड की जा चुकी है, जिन कॉलोनियों में बरसात का पानी भरा है, वहां, मडपंप लगाकर पानी की निकासी की जा रही है।

शहर में लगातार हो रही बारिश से बोराज तालाब लबालब होने से पाल में आई दरार और रिसाव की सूचना मिलने पर एडीएम सिटी गजेन्द्र सिंह राठौड़ ने मौके पर पहुंचकर हालात का निरीक्षण किया। उनके साथ प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों की टीम मौजूद रही। एनडीआरएफ और सिविल डिफेंस की टीमें भी तैनात की गई हैं। राठौड़ ने बताया कि तालाब की पाल पर लगातार नजर रखी जा रही है और एहतियात के तौर पर डूब क्षेत्र फायसागर रोड स्थित स्वास्तिक नगर कॉलोनी के करीब 80 मकानों को खाली कराया है, प्रभावित परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है।

सुप्रीम कोर्ट ने ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

करते हुए कहा, "उत्तराखंड, हिमाचल और पंजाब में हमने अभूतपूर्व भूस्खलन और बाढ़ देखी है। पंजाब की तस्वीरों में तो पूरे के पूरे गांव और खेत उजड़ चुके हैं। विकास जरूरी है, लेकिन संतुलन भी जरुरी है।"

"प्रकृति के साथ छेड़छाड़ अब पलटकर सामने आ रही है"

सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता को पीठ ने मामले को गंभीरता से लेने को कहा। न्यायालय ने टिप्पणी की, "एसजी साहब, कृपया इस पर ध्यान दें। यह एक गंभीर मामला प्रतीत होता है। भारी मात्रा में लकड़ी के लट्ठे बहते देखे गए हैं, जो पेड़ों की अवैध कटाई को दर्शाते हैं।" मेहता ने अदालत को आश्वासन दिया कि वे तुरंत पर्यावरण मंत्रालय के सचिव और संबंधित राज्यों के मुख्य सचिवों से बात करेंगे। उन्होंने स्पष्ट कहा, "हमने प्रकृति के साथ इतनी छेड़छाड़ कर दी है कि अब प्रकृति उसका जवाब दे रही है।"

अदालत यह सुनवाई एक जनहित याचिका (पीआईएल) पर कर रही थी, जो अनामिका राणा द्वारा दायर की गई थी। याचिका में हिमालयी क्षेत्रों में बार-बार होने वाली आपदाओं के मद्देनज़र रोकथाम और सुधारात्मक उपायों के लिए निर्देश मांगे गए थे। याचिका में कहा गया है कि केंद्र और राज्य, दोनों के पास आपदा प्रबंधन के लिए समर्पित संस्थाएं हैं, फिर भी वे प्रभावी योजना बनाने और लागू करने में विफल रहे हैं। इसके परिणामस्वरूप नुकसान की मात्रा और आपदाओं की घटनाएं लगातार बढ़ रही है।

याचिका में विनाश की तीव्रता बढ़ाने वाले कई कारणों की ओर संकेत किया गया – जैसे पहाड़ी सड़कों के लिए निर्धारित नियमावली की अनदेखी, जल स्रोतों पर अतिक्रमण, और पर्यावरणीय सुरक्षा उपायों का पालन न किया जाना।

याचिका में यह आरोप लगाया गया कि पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय तथा जल शक्ति मंत्रालय हिमालयी क्षेत्र की नाज़ुक पारिस्थितिकी और नदियों की सुरक्षा करने के अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने में विफल रहे हैं।

याचिका में विशेष जांच दल के गठन की मांग की गई है, जो पर्यावरणीय कानूनों और सड़क निर्माण दिशा-निर्देशों के उल्लंघन की जाँच करे।

इसमें राजमार्ग और सड़क निर्माण परियोजनाओं में हुई गड़बड़ियों और अधिकारियों की भूमिका की जांच की मांग की गई है, तथा स्वतंत्र विशेषज्ञ समिति का गठन करने की बात भी कही है, जो भूस्खलन वाले क्षेत्रों में भूवैज्ञानिक, भू-तकनीकी, पर्यावरणीय और पारिस्थितिकी संबंधी जांच करे।

याचिका में हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र की पुनर्स्थापना के लिए उपायों की सिफारिश करने की इच्छा जताई गई है, ताकि नागरिकों के मौलिक अधिकारों (अनुच्छेद 14 और 21) की रक्षा हो सके।

नेता प्रतिपक्ष ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

कोई ठोस कदम नहीं उठाया। बुढ़ानिया ने आरोप लगाया कि सरकार के मंत्री हेलिकॉप्टर से दौरे कर रहे हैं, लेकिन किसानों की सुध नहीं ले रहे। उन्होंने कहा कि गोदामों में पानी भर गया है, कई इलाके जलमग्न हैं, पर सरकार मूकदर्शक बनी हुई है।

नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि किसानों की फसलें दो बार बर्बाद हो चुकी हैं, लेकिन गिरदावरी तक के आदेश नहीं दिए गए। उन्होंने कहा कि सरकार के कानों के पर्दे खुल जाएं, इसलिए वे जोर से बोल रहे हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री पर भी कटाक्ष करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री सदन में आए जरूर, लेकिन कुछ समय बाद बिना कोई घोषणा किए चले गए।

विधानसभा में जब आपदा राहत मंत्री डॉ. किरोड़ीलाल मीणा ने स्थगन प्रस्तावों का जवाब देना शुरू किया, तभी विपक्ष का हंगामा शुरू हो गया। कांग्रेस विधायक अशोक चांदना बिना अनुमति के बोलने लगे, जिस पर स्पीकर ने आपत्ति जताई। इसके बाद कांग्रेस और भाजपा विधायकों के बीच नोकझोंक शुरू हो गई। स्पीकर ने बार-बार कांग्रेस विधायकों से शांत रहने की अपील की, लेकिन कोई असर नहीं हुआ।

आपदा राहत मंत्री डॉ. किरोड़ी लाल मीणा ने बताया कि अब तक 26 मृतकों के परिजनों को 1.04 करोड़ रुपये का मुआवजा बांटा जा चुका है। 22 जिलों में असामान्य, 16 जिलों में अतिरिक्त और 3 जिलों में सामान्य बारिश दर्ज की गई है।

■ **सदन की कार्यवाही दो बार स्थगित करनी पड़ी। दूसरी बार की कार्यवाही महज 33 मिनट ही हुई। हंगामे में सरकार ने तीन बिल पास कराये।**

स्पीकर ने कांग्रेस विधायकों को फटकार लगाते हुए कहा कि सरकार की तरफ से जवाब दिया जा रहा था, लेकिन आपने सुना ही नहीं। वैल में आकर विधायकों ने मिसबिहेव किया, जो बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में विरोध का अधिकार है, लेकिन उसकी भी मर्यादा होती है।

हंगामे और नारेबाजी के बीच विधानसभा की कार्यवाही पहले दोपहर 12:34 बजे स्थगित की गई, और दोपहर 2 बजे दोबारा शुरू होने पर, फिर से हंगामे के कारण 33 मिनट बाद स्थगित कर दी गई। अब सदन की अगली बैठक 8 सितंबर को होगी।

राजस्थान की राजनीति में यह घटनाक्रम किसानों की समस्याओं और सरकार की प्रतिक्रिया को लेकर गहराते राजनीतिक संघर्ष का संकेत है। जहां सरकार दावा कर रही है कि हर पीड़ित को सहायता दी जाएगी, वहीं विपक्ष इसे नाकाफी बताते हुए, सड़कों से लेकर सदन तक प्रदर्शन कर रहा है।

कांग्रेस को "...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

उन्होंने कहा, 2018 से अब तक 7 साल हो गए। वायदे के मुताबिक म्युनिसिपल वेस्ट से या लकड़ी के बुरादे से एक लीटर एथेनॉल भी नहीं बनाया है। और जो 627 करोड़ लीटर एथनॉल बना है, उसमें से 56 प्रतिशत गन्ने से बना है और बाकी अनाज से बना है। कुल 627 करोड़ लीटर एथनॉल में से एक लीटर भी म्युनिसिपल वेस्ट से नहीं बना। ये शॉकिंग है और बहुत हैरान कर देने वाला आंकड़ा है। जहां तक पर्यावरण के दावे हैं उनकी चौंकाने वाली सच्चाई कुछ और है। एक लीटर एथनॉल बनाने के लिए तीन हजार लीटर पानी की खपत होती है। ये दूसरा चौंकाने वाला आंकड़ा है। खेड़ा बोले, हमें कहा गया कि साहब एथनॉल से माइलेज बहुत अच्छा होगा और रख रखाव की चिंताएं हैं, खत्म हो जाएंगी पर उल्टा हुआ। नीति आयोग तक माइलेज में 6 प्रतिशत गिरावट स्वीकार करता है, लेकिन हकीकत तो और ज्यादा है। वर्ष 2023 से पहले जितने इंजन हमारे यहाँ बने हैं, वे इंजन डैमेज हो रहे हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता के अनुसार इससे पर्यावरण प्रदूषण बढ़ रहा है गाड़ियों का माइलेज कम हो रहा है कि एथनॉल की जो डिस्टीलरीज़ होती है वो रैड कैटगरी में आती हैं प्रदूषण फैलाने में आगेहोती हैं।

एस. आई. भर्ती ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

मिलकर पेपर लीक गैंग के सदस्य विनोद कुमार जाट उर्फ विनोद रेवाड़ से एसआई भर्ती परीक्षा-2021 का लिखित परीक्षा का लीक सॉल्वड पेपर का आठ लाख रुपए में सौदा किया था। दोनों परियों का लीक सॉल्वड पेपर विनोद कुमार रेवाड़ के जरिए कार्तिकेय शर्मा के मोबाइल पर व्हाट्सएप पर लिया था। लीक सॉल्वड पेपर को पढ कर रिंकू यादव ने एसआई भर्ती परीक्षा की लिखित परीक्षा दी थी। लिखित परीक्षा में हिन्दी विषय में 126.01 और सामान्य ज्ञान विषय में 160.65 अंक, इस प्रकार कुल 286.66 अंक प्राप्त किए थे। लेकिन अंतिम रूप से रिंकू यादव का चयन नहीं हुआ। एसओजी ने प्रकरण में अब तक 55 प्रशिक्षु उपनिरीक्षक सहित कुल 126 आरोपितों को गिरफ्तार किया है।

हाई कोर्ट ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

सचिव है। संघ के अध्यक्ष रहे महावीर रांका के खिलाफ सहकारिता विभाग में शिकायत दी गई थी और उन्हें पद से हटाया गया था। वहीं, याचिकाकर्ता ने सहकारिता विभाग में प्रार्थना पत्र पेश कर चुनाव कराने की मांग की थी, जिसे यह कहते हुए खारिज कर दिया कि संघ की जांच विभाग में लंबित चल रही है। याचिका में कहा गया कि इसके बावजूद, बीकानेर में चुनाव कराने के लिए विज्ञप्ति का प्रकाशन कराया गया है।

जी.एस.टी. 2.0 ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

सुधार की कोशिशें पहले से चल रही थीं, लेकिन, मौजूदा आर्थिक हालात में इन्हें तुरंत लागू करने की ज़रूरत महसूस हुई।

उम्मीद है कि कई वस्तुओं पर टैक्स रेट्स में कटौती और स्लैब पुनर्गठन से घरेलू खपत बढ़ेगी। यह इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत के एक बड़े निर्यात बाज़ार (अमेरिरका) में कठिनाइयाँ बढ़ रही हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प की टैरिफ नीति से भारतीय उत्पाद अमेरिकी बाज़ार से बाहर हो सकते हैं। कपड़ा और परिधान जैसे बड़े निर्यात क्षेत्र पहले से दबाव में हैं और इन क्षेत्रों में रोज़गार तेजी से घट रहा है।

कर कटौती से घरेलू माँग को बढ़ाकर विदेशी बाज़ारों में हुए नुकसान की भरपाई की जा सकती है। यही तर्क अमेरिका ने पूर्व राष्ट्रपति रीगन के दौर में अपनाया था, जब कर कटौती ने उनकी अर्थव्यवस्था को मजबूती दी थी। इसी तर्क पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को उम्मीद है कि मोटर कार से लेकर दूध उत्पादों तक, टैक्स घटने से घरेलू माँग बढ़ेगी। प्रधानमंत्री भी यही कहते रहे हैं कि सरकार कम कर दरों के ज़रिए लोगों के पास अधिक पैसा छोड़ रही है ताकि वे अधिक उपभोग पर खर्च कर सकें।

अगर घरेलू खपत बढ़ती है तो यह फायदेमंद हो सकता है। अधिक खपत से उत्पादक निवेश बढ़ाएँगे, निवेश से रोज़गार पैदा होगा और फिर विकास की गति तेज होगी। लेकिन आलोचक कहते हैं कि भारत के निजी क्षेत्र का इतिहास बताता है कि बढ़ती माँग हमेशा बड़े निवेश और रोज़गार में नहीं बदलती। हाल के वर्षों में भी निजी निवेश कमज़ोर रहा है और केवल सरकार के बड़े बुनियादी ढाँचे के प्रोजेक्ट्स ने अर्थव्यवस्था को सहारा दिया है।

अगर माँग बढ़ी लेकिन आपूर्ति नहीं बढ़ी तो इसका नतीजा महँगाई हो सकती है और यह दुष्चक्र का रूप ले सकती है और संतुलन बिगाड़ सकती है। यह भी एक संभावना है। फिर भी, रोज़मर्रा की चीज़ों पर कर में बड़ी कटौती से अर्थव्यवस्था को गति मिल सकती है और निजी निवेश बढ़ सकता है। खासकर मौजूदा समय में, जब निवेश के अवसर खुले हैं और विदेशी कंपनियाँ भारतीय बाज़ार में निवेश करने आ रही हैं। हाल ही में मोबाइल फोन से लेकर मोटर कार तक विदेशी निवेश में तेजी आई है।

■ **निराशावादियों की इस आशंका के बावजूद वित्त मंत्री ने एक हिम्मत वाली रणनीति अपनाई है और भगवान करे उनका यह रिस्क कामयाबी में तब्दील हो।**

ये वैश्विक कंपनियाँ भारत में विश्वस्तरीय निर्माण कर रही हैं और घरेलू व अंतरराष्ट्रीय बाज़ारों में अपनी जगह बना रही हैं। साथ ही, ये बेहतर आय वाले रोज़गार भी पैदा कर रही हैं।

इसलिए मौजूदा सुधारों को सिर्फ कर सुधार नहीं बल्कि सार्वजनिक वित्तीय ढाँचे के बड़े सुधार के रूप में देखना चाहिए। इन्हें मौजूदा भू-आर्थिक हालात और देश पर उनके असर के संदर्भ में समझना होगा। इस दृष्टि से देखें तो यह बदलाव समयानुकूल है और विकास को नई दिशा दे सकता है। अब बस इंतज़ार करना होगा कि नतीजे कैसे सामने आते हैं।

दिल्ली ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

प्रभावित हैं। वासुदेव घाट, निगम बोध घाट, मोनेस्ट्री और मजनूं का टीला भी पानी में डूब गये हैं। बाढ़ प्रभावित इलाकों में नाव चल रही है।

जमानती ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

मजिस्ट्रेट और एडीजे क्रम-6 महानगर द्वितीय की ओर से अदालती आदेश की पालना में अपना स्पष्टीकरण पेश किया, लेकिन अदालत उससे संतुष्ट नहीं हुई। अदालत ने कहा कि न्यायिक अधिकारी अपने स्पष्टीकरण में बता रहे हैं कि प्रकरण में गैर जमानती अपराध के तत्व मौजूद थे, लेकिन जमानत खारिज करने के आदेश में इसका कोई उल्लेख नहीं है।

अदालत ने कहा कि न्यायिक अधिकारियों ने मशीनी अंदाज में जमानत प्रार्थना पत्रों का निस्तारण किया। जमानती अपराध में जमानत को अधिकार का विषय माना जाता है, न कि न्यायिक अधिकारी के विवेक का। अदालत ने कहा कि पहली बार जब आरोपी को पेश किया जाता है तो मजिस्ट्रेट के लिए यह अनिवार्य है कि वह सभी दस्तावेजों और साक्ष्य पर विचार करे। इस प्रकरण में जांच अधिकारी, दोनों पक्षों के वकील और न्यायिक अधिकारी अपने कर्तव्य के निर्वहन में विफल रहे हैं। कुछ हद तक यह कोर्ट भी याचिकाकर्ताओं की हिरासत के लिए जिम्मेदार है, क्योंकि बड़ी संख्या में जमानत याचिकाओं के लंबित होने के कारण वह प्रकरण को प्राथमिकता से नहीं ले सका।

याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता राजेश महर्षि ने बताया कि चित्रकूट थाना पुलिस ने प्रॉपर्टी डीलर को दुष्कर्म के मामले में फंसाने की धमकी देकर उससे तीन लाख रुपए का चेक लेने के आरोप में याचिकाकर्ताओं को गिरफ्तार किया था। दोनों आरोपी 16 जून, 2025 से न्यायिक अभिरक्षा में थीं। जमानती अपराध के बावजूद, उन्हें जेल में रखा गया। वहीं हाईकोर्ट ने उन्हें गत तीस जुलाई को जमानत दी थी।

एम. आई. रोड पर सड़क धंसने से 20 फीट गहरा गड्ढा बना

कहा जा रहा है कि सीवरेज लाइन के नजदीक मिट्टी का कटाव होने से गवरमैंट हॉस्टल चौराहे पर यह गड्ढा बना

-कार्यालय संवाददाता-

जयपुर, 4 सितंबर। । राजधानी जयपुर में मिर्जा इस्माइल रोड (एम.आई.रोड) पर गर्वमेंट हॉस्टल चौराहे के पास गुरूवार सुबह सड़क धंसने से 20 फीट गहरा गड्ढा हो गया। गनीमत रही कि उस वक्त घटनास्थल से कोई वाहन नहीं गुजर रहा था, अन्यथा जनहानि हो सकती थी। बताया जा रहा है कि जयपुर में बीते 4 दिनों से हो रही तेज बारिश के कारण सीवरेज लाइन के नजदीक मिट्टी का कटाव हो गया और गुरूवार सुबह करीब सवा 9 बजे यहां पर करीब 20 फीट गहरा और 10 फीट चौड़ा गड्ढा बन गया। इस घटना के बाद मौके पर हड़कंप मच गया। चौराहे पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने दौड़कर मोर्चा संभाला और बैरिकेड्स लगाकर आसपास आवाजाही रोकी। देखते ही देखते गड्ढे ने विशाल रूप ले लिया, सूचना पाकर नगर निगम हैरिटेज की टीम भी मौके पर पहुंची और मिट्टी का कटाव रोकने और गड्ढा भरने के प्रयास में जुट गई। इस हादसे के बाद एम.आई. रोड पर दिनभर भारी ट्रैफिक जाम लगा रहा, दिनभर यहां से वाहन रेंगते हुए आगे बढ़े।

■ **चौराहे पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने दौडकर मोर्चा संभाला और बैरिकेड्स लगा कर ट्रैफिक रोका। देखते ही देखते गड्ढा बढ़कर 20 फीट गहरा व 10 फीट चौड़ा हो गया।**

जयपुर में लगातार हो रही बारिश से एम.आई. रोड पर गर्वमेंट हॉस्टल चौराहे के पास गुरूवार सुबह सड़क धंस गई जिससे 10 फीट चौडा और 20 फीट गहरा गड्ढा हो गया।

बताया जा रहा है कि राजधानी जयपुर में सीवरेज लाइनें करीब 50-60 वर्ष पुरानी हैं। टेलीकॉम कंपनियों द्वारा अंडरग्राउंड केबल्स डालने तथा सीवरेज लाइन के नजदीक छोटे-छोटे गड्ढों में से बारिश के पानी का रिसाव होने के कारण सड़क धंसी है। नगर निगम हैरिटेज की टीम ने सड़क में बने गड्ढे में से बारिश का पानी निकालकर आसपास खुदाई कार्य शुरू करवायी है, ताकि अगर कहीं और भी मिट्टी का कटाव हो तो मालूम चल सके।

नगर निगम के चेयरमैन उत्तम शर्मा ने कहा कि लगातार हो रही बारिश के बाद सीवरेज लाइन डैमेज हो गई थी, जिसकी वजह से सडक के मामूली गड्ढे ने विशाल रूप ले लिया। नगर निगम की टीम द्वारा पूरी मुस्तैदी के साथ गड्ढे को भरने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। जल्द ही गड्ढे को भरकर यातायात व्यवस्था फिर से सुचारू रूप से शुरू कर दी जायेगी।

किशनपोल जोन के सहायक अभियंता इमरान ने बताया कि पुरानी सीवरेज लाइन लीक होने की वजह से गवर्नमेंट हॉस्टल चौराहे पर गड्ढा हुआ था। फिलहाल निगम की टीम द्वारा गड्ढे को खाली कर मरम्मत का काम शुरू कर दिया गया है। जल्द ही इस गड्ढे को फिर से ठीक करके सड़क बना दी जायेगी। इस कार्य में 2 से 3 दिन का समय लगने की संभावना है।

राष्ट्रदूत (एच.यू.एफ.) के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक सोमेश शर्मा द्वारा वतन प्रेस, सुधर्मा, एम.आई.रोड, जयपुर एवं सुधर्मा-II, लालकोठी शॉपिंग सेंटर, टोंक रोड, जयपुर से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादकः- राजेश शर्मा । आर.एन.आई. नं. 3641/57, ई-मेल-rastrdut@gmail.com कोटा कार्यालयः-पलायथा हाउस, छत्रपति शिवाजी मार्ग, कोटा। फोन:2386031, 2386032, फैक्स:0744-2386033 बीकानेर कार्यालयः-कुम्भाना हाउस, हनुमान हत्था, बीकानेर। फोन:2200660, फैक्स: 0151-2527371 उदयपुर कार्यालयः-आयड, मेन रोड आयड, उदयपुर। फोन: 2413092, 2418945, फैक्स: 0294-2410146 अजमेर कार्यालयः-घूघरा घाटी, जयपुर रोड,अजमेर। फोन: 2627612, फैक्स:0145-2624665 जालोर कार्यालय :- जी 1/63, इन्डस्ट्रीयल एरिया, फेस प्रथम, जालोर। फोन: 226422, 226423, फैक्स: 02973-226424 हिण्डौनसिटी कार्यालय :- जी -1-201, रीको औद्योगिक क्षेत्र, हिण्डौनसिटी। फोन: 230200, 230400, फैक्स: 07469-230600 चूरू कार्यालयः एच-150, रीको औद्योगिक क्षेत्र, चूरू, फोन: 256906, 256907, फैक्स:01562-256908